Government of Bihar
Department of Environment and Forests

ACTION ON CLIMATE TODAY

PRESS RELEASE
Embargoed24 June 2018

प्रकाशनार्थ

पटना, 24 जून 2018. बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने अपने बौद्धिक साझीदारों-यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआइडी) के तहत कार्यरत ऍक्शन ऑन क्लाइमेट टूडे (ऍक्ट) और पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के तहत (भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में) कार्यरत सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज (सीईईसीसी) -के साथ मिलकर 'पूर्वी भारत जलवायु परिवर्तन कनक्लेव' नामक उच्चस्तरीय परिषद का आयोजन किया। माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने आज पटना में आयोजित छत्तीसगढ़, असम, ओडिसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों के साथ मिलकर ''जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोधक्षमता-संपन्न पूर्वी भारत उच्चस्तरीय परिषद : मंत्री नेटवर्क'' का उद्घाटन किया। आज आरंभ हुए कनक्लेव में भारत के पूर्वी क्षेत्र के नीति निर्माता, सरकारी उच्चाधिकारी, निर्णयकर्ता और उद्योगपति तथा वैश्विक, राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय और गैर-सरकारी विशेषज्ञ विचार-विमर्श करने तथा जलवायु के मामले में प्रतिरोधक्षमता-संपन्न राष्ट्र के निर्माण पर सबकों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ शामिल हुए।

श्री नीतीश कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि ''जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बिहार में सबसे अधिक महसूस किए जा रहे हैं जबकि इस मामले में बिहार की भूमिका सबसे कम है। बिहार ने इसमें किसी भी तरह से योगदान नहीं किया है, तब भी राज्य को बार-बार आने वाली बाढ़ और सूखा का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है।'' उन्होंने राज्य के दो सबसे बड़े जल निकायों -गंगा और कोशी में गाद जमा होने के मुद्दे को प्रमुखता से सामने लाया और सुझाव दिया कि गाद हटाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है; समस्या का समाधान उसे समुद्र तक पहुंचाने से हो सकता है।

कनक्लेव की प्रशंसा करते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि पूर्वी भारत की ओर देखना सबसे जरूरी है क्योंकि अपनी भौगोलिक और पारिस्थितिकीय विविधता के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के मामले में यह क्षेत्र सर्वाधिक असुरक्षित है। पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए डॉ. वर्धन ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को निर्धारित समयसीमा के पहले ही हासिल कर लेगा। उन्होंने सबसे हरित सुव्यवहार को अपने मन में बिठाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के विशेषज्ञों और व्यवहारकर्ताओं को एक साथ लाने वाले कनक्लेव से पूर्वी भारत को ही नहीं, पूरे देश को मदद मिलेगी।

बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार ने कहा कि ''हमे खुशी है कि बिहार को 'पूर्वी भारत जलवायु परिवर्तन कनक्लेव' के आयोजन का अवसर मिला है। वर्ष 2015 में सीओपी समझौते ने 195 देशों में एक साथ आते और उत्सर्जन में कमी लाने तथा ऐसी रणनीतियां अपनाने के लिए वचनबद्धता प्रकट करते देखा था जो सीमांतकृत समुदायों और कृषिनिर्भर समाजों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों। भारत पेरिस शिखर सम्मेलन में किए गए अपने संकल्पों को पूरा करने में नहीं हिचकेगा; और खास तौर पर बिहार तो जलवायु के लिहाज से उचित कार्रवाइयां करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि बिहार 2022 तक 2000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा, जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की स्थापना करेगा और जलवायु के अनुकूल कृषि के जरिए जलवायु के अनुकूल (क्लाइमेट-स्मार्ट) गांवों का विकास करेगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि 'विश्व स्तर पर चिंतन, स्थानीय स्तर पर कार्रवाई' जलवायु संबंधी हमारी सारी कार्रवाइयों का मूल मंत्र होना चाहिए।

दो दिन चलने वाले कनक्लेव में जलवायु परिवर्तन अभिशासन, जलवायु वित्तपोषण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु-सक्षम जल प्रबंधन तथा जलवायु-सक्षम जलवायु एवं मौसम संबंधी सेवाओं के लिए निर्णय सहयोग प्रणाली के मामले में ताजातरीन रुझानों, व्यवहारों, और चुनौतियों पर साझा समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें व्यवस्था सुधार, संस्थागत विकास और नीतिगत परिवर्तनों के जरिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन संबंधी मुद्दों पर शासन में सुधार के लिए विधियों और दृष्टिकोणों की तलाश का भी प्रयास होगा। कृषि, जल, विद्युत, वित्त और आपदा जोखिम न्यूनीकरण आदि क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को मुख्य धारा में लाना तथा उनके लिए दृष्टिकोण और क्रियाविधियों का विकास करना कनक्लेव का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है।

साथ ही, कनक्लेव में योजना और नीति निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने के लिहाज से पूर्वी भारत के राज्यों के बीच अनुकूलन क्षमता के निर्माण और राज्यों विचार-विनिमय के संभावित अवसरों को चिन्हित करने के तरीके खोजने पर भी चर्चा की जाएगी।

अबिनाश मोहंती
निदेशक,
सीईईसीसी, आद्री
मोबाइल : +91 9776478313